

सरना कोड के लिए 30 के भारत बंद का दिखेगा व्यापक असर

जागें नहीं तो हमें जबरन हिंदू मुसलमान, इसाई बनने को भजबूर हाना पड़ेगा

आदिवासियों को धार्मिक आजादी से बंधित करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों

नवीन मेल संवाददाता। रांची

केंद्रीय सरना समिति की बैठक शनिवार को कर्मदोतों द्वारा धूमकुड़िया भवन में हुई। बैठक में सरना कोड की मांग को लेकर तीस दिसंबर के भारत बंद बनाने का नियम लिया गया। बैठक में आदिवासी संगठन अभियान, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी छात्र संघ, सरना धर्म समन्वय समिति (खट्टी), अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आदि के प्रतीतनी शामिल हुए। फूलचंद तिर्की ने कहा कि जब 1951 की जनगणना तक आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कलम कोड था तो उसे कांग्रेस पार्टी ने खट्टी हड्डावा और अब भाजपा जोर जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू का ठप्पा क्यों लगाना चाहती है। अतः हमें पार्टियों और नेताओं से ज्यादा जनता और अंदोलन पर



भरोसा करना पड़ेगा। बोडोलैंड आंदोलन की तरह जीत हासिल करनी होगी। हाल के गुमला, लोहरदगा, खट्टी की बैठकों में भारत बंद के प्रति जनता का मजबूत समर्थन दिया। हमें सालखन मुर्म की अगरवाल पर विकास अधिकारी के रूप से शामिल पूर्व सांसद और अधिकारी के रूप से अगरवाल भाजपा ने खट्टी कोड को लिए और भरोसा है। हम जलूर सफल होंगे। मुख्य अधिकारी के रूप से शामिल पूर्व सांसद और संगठन के गढ़ीय अध्यक्ष सालखन मुर्म ने कहा की हम हारा नारा हैं-जो सरना कोड देगा, आदिवासी उम्मीदों को बोट देगा। सालखन मुर्म ने अगे कहा सरना आंदोलन बहुद आदिवासी एकता का आंदोलन है और भारत में आदिवासी राष्ट्र

स्थापित करने का भी आंदोलन है। आदिवासी छात्र संघ की तरफ से सुमित उरांव, मोनू लकड़ा, मोज उरांव ने भारत बंद के समर्थन में अपन सांस्कृतिक विचार रखे। संगठन की तरफ से मुमित्रा मुर्म, देवेशाराण्य मुर्म और चंद्र मोहन मार्डी ने विचार रखा। केंद्रीय सरना युवाओं को तरफ से एक तरफ से संजय उरांव, प्रमोद एकका, भनेशर लोहरा, अमर बिरामी, चदन पाहन ने विचार रखा। सरना धर्म समन्वय समिति की तरफ से विरसा कंडार ने भारत बंद का समर्थन किया।

सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, चार नाबालिंग निरुद्ध रांची। राजधानी की तुपुदाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के छह आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में चार नाबालिंग को निरुद्ध किया गया है जबकि दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में प्रशुत बाइक बरपाया किया है। सिटी एस्पोर्स राजकुमार मेहता ने शनिवार का संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नाबालिंग लाडी की गत पांच दिसंबर को गिरफ्तार को जोनार्सिंग में अपने ही गांव के रहने वाले दोस्त से मिलने के लिए आई थी। नौ दिसंबर को दोपहर से झाँगड़ा होने के बाद लाडी के अंकले ही शाम में जोनार्सिंग से पैदल सरनांजी होते हुए खुंटी को ओर जा रही थी। इसी मौके में नाबालिंग युवाओं को जोनार्सिंग के लिए आपने भरोसा की ओर बढ़ाया था। इसके बाद लाडी की गांधीरता को अंजाम दिया था। इस संबंध में आठ लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया। यामले की गांधीरता को देखते हुए द्वितीय लोगों गाजा कुमार मिश्र के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

एक नजर

मनी लान्ड्रिंग के आरोपी मुकेश मितल की अग्रिम बैल याचिका खारिज

रांची। ईडी के विशेष न्यायालय पांके शर्म की अदालत में टेंडर घोटाला के लिए अवैध करने और मनी लान्ड्रिंग करने के आरोपित मुकेश मितल की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमीन घोटाले के आरोपी प्रदीप बागची की बैल याचिका खारिज

रांची। जमीन घोटाले के आरोपित प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर ईडी के विशेष न्यायालय दिनेश कुमार राय की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत ने प्रदीप बागची की जमानत याचिका पर याचिका खारिज कर दी है। इसमें पूर्व गत 13 दिसंबर को ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुनने के लिए नियंत्रित की थी।

कोकर शिव मंदिर के

समीप अज्ञात शव मिला

रांची। रांची के सदर थाना बेटे के कोकर शिव मंदिर के समीप से शनिवार को एक अज्ञात शव का उपर्युक्त किया गया।

थाना को पोस्टमार्टम के लिए रिस्म भेज दिया गया है।

झारखंड प्रदेश डीजल

ऑटो चालक महासंघ ऑटो भंग

रांची। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश, जिला, महानगर, प्रांतिक और एवं कार्यकारिणी संस्थानों की बैठक हुई। महासंघ के संस्थान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एवं ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करना चाहता है, वह 25 तक प्रदेश कार्यालय में संस्थान प्रदेश के पास आवेदन कर सकते हैं।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन

राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता व संकल्प जरूरी

प्रदेश में 26 जनवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है

सभी जिलों को 366 आईईपी वेन उपलब्ध करायी गयी है

नवीन मेल संवाददाता। रांची

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि "विकसित भारत संकल्प यात्रा" एक प्रसिद्ध और सशक्त राष्ट्र के नियमण के प्रति प्रतिबद्धता एवं संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जरिये पांच राज्यों-मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नियमण के लिए कर के बैठक में अंतर्गत विकसित भारत बनाने के लिए एक बैठक आंदोलन की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता का मजबूत समर्थन दिया।



केंद्रीय मंत्री विकसित भारत कार्यक्रम में बुद्ध पुरुषे

हमारा संकल्प विकसित भारत कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय संसद सह केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा शनिवार को बुद्ध प्रखेड़ के उल्कमित उच्च विद्यालय नावाडी हग गढ़ी और राष्ट्रीय मार्ग-33 टोल प्लाजा सीमापूर एडलहाट पंचायत स्थित किटकेट मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

आर्थिक विकास में सहायता की ओर बढ़ाया गया। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा सहित प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रेस्टर्न मार्डी के विकास के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने के लिए "प्रधानमंत्री उत्तरांश योजना" शुरू किया गया। बेंगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अर्थिक रूप से उत्तरांश योजना के लिए गोपनीय कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि जनता के माध्यम से संस्कृति के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने के लिए "प्रधानमंत्री उत्तरांश योजना" शुरू किया गया। बेंगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अर्थिक रूप से उत्तरांश योजना के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने के लिए "प्रधानमंत्री उत्तरांश योजना" शुरू किया गया। बेंगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अर्थिक रूप से उत्तरांश योजना के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने के लिए "प्रधानमंत्री उत्तरांश योजना" शुरू किया गया। बेंगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अर्थिक रूप से उत्तरांश योजना के लिए एक बैठक की ओर बढ़ाया गया।

पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से होने वाले हानिकारक प्रभावों से मुक्त करने के लिए "प्रधानमंत्री उत्तरांश योजना" शुरू किया गया। बेंगरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ अर्थिक र

एक नजर इधर भी

‘कविता एक थैरेपी भी है’

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस बार हिन्दुस्तान टाइम्स साहित्य उत्सव-2023 में कविता की गूंज सुनाई दी। कविता पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। उत्सव का आयोजन कार्यक्रम के प्रमुख सहयोगी अर्डिटीएल पब्लिक स्कूल द्वारका के सभागार में किया गया। ख्यातिलब्ध कवियों और लेखकों का रचना पाठ और संवाद तो प्रभावी ही रहा। लेखकों की कार्यशाला, पेटिंग कथावचन और डडल गतिविधि ने भी श्रेताओं

पाटग, कवायावचन और डूडल गातावध न मा आताजी
का ध्यान खींचा। इस उत्सव का आगाज कविता की
समाज में भूमिका के आरंभिक सत्र से हुई। एपीजे
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ
आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के प्रोफेसर प्रोफेसर आनंद
खत्री, प्रख्यात कवि-ललित निवंधकार, आलोचक
तथा प्रोफेसर एवं नव नालंदा महाविहार सम
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर परिचय दास,
द्विभाषी कवयित्री एवं लेखिका सुनीता सिंह और रचना
पंत ने इस संदर्भ में अपनी प्रासारणीक कविताएँ सुनाईं।
पैनल चर्चा के बाद संवाद सत्र में विद्यार्थियों और युवा
कवियों ने अतिथियों से दिलचस्प सवाल पूछे। प्रोफेसर
आनंद खत्री ने काव्य-चेतना पर चर्चा की। सुनीता
सिंह ने कविता को मन व जीवन की जरूरत बताया।
प्रोफेसर परिचय दास ने अपने ललित वक्तव्य में
कविता को अपने आप में एक उत्सव के रूप में
वर्णित किया। उन्होंने कहा कि कविता मनुष्य के
अन्तर्मन की विषनाशिका और मुकिदायिनी है। कविता
आत्मालाप व सामाजिक संवाद यानी दोनों की हेतु है।
यह भीतर के उपचार का सबसे बड़ा माध्यम है।
उन्होंने कविता को सबको जोड़ने, नकार से विरत होने
व भावना की सर्सिद्धि कहा। प्रो. परिचय दास ने कहा
कि वह अंदर की ललय है। इसलिये सबसे बड़ी थेरेपी
है। उन्होंने कहा कि अपनी रचना-प्रक्रिया में मैंने
आत्म संघनन व बाहर के वैष्य को प्रमुख आधार के
रूप में देखा है। रचना पंत ने विद्यार्थियों को याद
दिलाया कि सहित्य और कविता परामर्शी की
आवश्यकता को दूर कर देती है। इसलिए बच्चों को
सिर्फ तकनीक की ओर नहीं भागना चाहिए।
भावनात्मक रूप से परिपक्व होने और जीवन और
देखने के लिए जीवन की जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी

भावनाओं को समझने की बारीकियों के लिए साहित्य आवश्यक है। उन्होंने सुआव दिया कि छात्रों को एक समान बने रहने के लिए रुड्यार्ड किपलिंग की कविता पढ़नी चाहिए। इस सत्र के बाद इन विटेनीन द लाइंस नाम से एक और इंटरैक्टिव पैनल- चर्चा हुई। इसमें अतिथि लेखकों में सुनीता पंत बंसल, डॉ. हषार्ली सिंह, उपभोक्ता मंच की सदस्य न्यायाधीश और कवियत्री प्रेरणा जैन ने हिस्सा लिया। सत्र का संचालन वेंटेश्वर इन्टरनेशनल स्कूल द्वारका की प्रिसिपल मनीषा शर्मा ने किया। डॉ. हषार्ली सिंह ने अपनी आने वाली किताब 'अनारकली' के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह इस विषय के प्रति आकर्षित हुई। सुनीता पंत बंसल ने पौराणिक कहानियों के साथ अपनी यात्रा के बारे में बात की। इस उत्सव का आकर्षक कार्यक्रम 'द ह्यूमन लाइब्रेरी' रहा। यह ऐसा मंच है जिसमें छात्र अपनी अनूठी कहानियों और अनुभवों को साझा करते हुए 'मानव पुस्तक' बन जाते हैं। यह मंच रुद्धिवादिता का तोड़ता है। लोगों को व्यक्तिगत कथाओं के माध्यम से जुड़ने की अनुमति देकर समझ को बढ़ावा देता है। इसे सहयोगात्मक स्टेरी टेलिंग डूडल गतिविधि के रूप में देखा गया। दिल्ली इन्टरनेशनल स्कूल द्वारका की प्राचार्य अनुभा श्रीवास्तव ने कहा कि कथा-वाचन की कला को और भी गति देने की आवश्यकता है। सीबीएसई संकल्प सहोदय (एसडब्ल्यू) दिल्ली की अध्यक्ष और आईईएल पल्लिक स्कूल की प्रिसिपल डॉ. सुधा आचार्य ने साहित्य उत्सव का हिस्सा बनाने के लिए आयोजक और सूत्रधार अखबार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साहित्य हमेशा आत्मा का भोजन होता है। इस उत्सव ने इस तरह के आयोजन से आने वाले नये विचारों और जुड़ाव को देखने का एक अवसर और मंच प्रदान किया। इससे विद्यार्थियों को अमूर्त विरासत, रोमांचक विचारों और बहुत करीबी अनुभव से साहित्य को जानने का मौका मिला (लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।

मुक्त

यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाने पर सहमति

वैश्विक स्तरपर रूस-यूक्रेन व इजरायल-हमास युद्ध से दुनियां को आभास हो चुका है कि दुनिया अब तीन खेमों में बट चुकी है, इसे और भी स्पष्ट रूप से देखें तो दुनियां की दो महा शक्तियों के पक्ष विपक्ष में और कुछ देश अपने आप को न्यूट्रल रूप से रखे हुए हैं, जो हमें संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम या अन्य मुद्दों पर वोटिंग में देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत ने हमेशा न्यूट्रल स्थिति अपना कर रखी है और वोटिंग में अनुपस्थित रहा है परंतु दो दिन पहले ही भारत ने यूएन महासभा में फौरन मानवीय युद्ध विराम व बंधकों को रिहाई के मामले पर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था उधर अमेरिका ने भी इसराइल को सख्त चेतावनी दी है कि अपना रुख बदले अन्यथा गाजा युद्ध के लिए समर्थन खो देगा यानी भारत अमेरिका की वर्तमान मंशा को देखा जाय तो इसमुद्दे पर दोनों देशों की आम सहमति झलकती है, इसलिए ही दोनों की मैत्री जग प्रसिद्ध है परंतु मेरा मानना है कि दोनों देशों को मिलकर उपरोक्त दोनों नामित युद्धों को रोकने के लिए अगे आना चाहिए परंतु इसके विपरीत दिनांक 14-15 दिसंबर 2023 को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को यूरोपीय संघ जिसमें 27 सदस्य देश हैं उसमें सदस्य बनाने की महत्वपूर्ण सहमति दे दी है,

जिससे रूस यूक्रेन युद्ध मामले में धंघे में तेल डालने का काम होगा इसपर चीन की मुश्किलें बढ़ना तय है क्योंकि अगर यूक्रेन ईयू का सदस्य देश बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से उसके समर्थन में खुलकर 27 देश भी आ जायेंगे, हालांकि हंगरी ने इसका विरोध किया है। परंतु अभी केवल एयर संघ की सहमति ही मिली है, अर्थात् अनेक प्रक्रियाएं होना बाकी है जिसमें कुछ वर्ष भी लग सकते हैं तब तक ऊंट कहां करवट बदलेगा पता नहीं चूकि हमें युद्ध रूपी आग में उकसावे रूपी घी नहीं डालना है, बल्कि युद्ध विराम करना है, इसलिए आज हम मीडियम उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे। भारत अमेरिका के आगे आकर रूस-यूक्रेन इसराइल-हमास युद्ध को समाप्त करने आम सहमति बनवाना मानवीय कल्याण के लिए जरूरी है। साथियों बात अग्रणी हम यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने पर सहमति की करें तो, ब्रेसल्स में, 14 दिसंबर यूरोपीय संघ ने यूक्रेन और मोल्दोवा को सदस्य के रूप में शामिल करने पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को सहमति जताई। रूस के साथ युद्ध लड़ रहे यूक्रेन के लिए यह एक बड़ी राहत वाली खबर साबित हो सकती है। यूक्रेन लंबे समय से 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शामिल होने का इच्छुक रहा है। यूरोपीय संघ के 27

नेताओं के ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन वेंडैरान दोनों देशों को सदस्य देश वें रूप में शामिल करने के लिए चर्चा करने के संबंध में निर्णय लिया गया। जब यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस संबंध में सदस्यता वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई। यह यूक्रेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है। वह भी ऐसे



भारत अमेरिका को आगे इसराइल-हमास युद्ध को सम्बन्धाना मानवीय कल्याण वें को यूरोपीय संघ में शामिल करें तो, ब्रसेल्स में, 14 दिसंबर और मोल्दोवा को सदस्य के पर चर्चा के लिए बृहस्पतिव रूस के साथ युद्ध लड़ रहे रुस के साथ युद्ध लड़ रहे बड़ी राहत वाली खबर से



पहले कहा था कि वह इस तरह ने समझाते को रोक देंगे। ओर्बन ने पुरुषों की किंवदन्ति की जिसके अनुसार उन्होंने खराब निर्णय कहा था। इस स्तर पर यह स्पष्ट नहीं था कि बदले में उन्होंने वास्तव में क्या मिल सकता है। ऐसे ही इस तरह के निर्णय को मंजूरी देने वाले आकर रूस-यूक्रेन संघरण करने आम सहमति लिए जरूरी है। यूक्रेन करने पर सहमति की यूरोपीय संघ ने यूक्रेन रूप में शामिल करने का को सहमति जताई। यूक्रेन के लिए यह एक बित हो सकती है।

असामान्य माना जा रहा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, यह यूक्रेन के लिए एक जीत है। पूरे यूरोप के लिए एक जीत है। एक जीत जो प्रेरित करती है। प्रेरणा देती है और मजबूत करती है। आगे कहा कि मैं इस दिन प्रत्येक

A portrait photograph of Kishan Bhavnani Gordiya. He is a middle-aged man with dark hair, wearing a dark suit jacket, a white shirt, and a patterned tie. He is looking directly at the camera with a slight smile.

के लिए चर्चा करने के संबंध में निर्णय लिया गया। यूक्रेन को सदस्यता देने के लिए यूरोपीय संघ वार्ता शुरू करने पर हुआ सहमत हो गय है, कोव को मिली अप्रत्याशित सफलता। साथियों अंगर हम हंगरी के वोटिंग से दूर रहने की करें तो, हंगरी के बात पीएम क्षण भर के लिए कमरे से चले गये, जबकि अन्य 26 नेता वोट के लिए आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो सदेश के साथ अपने सहयोगियों से दूरी बना ली। यूक्रेन की यूरोपीय संघ की सदस्यता एक बुरा निर्णय है। हंगरी इस गतत फैसले में भाग नहीं लेना चाहता है, और इसलिए आज इस निर्णय से दूर रहा। यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य हंगरी ने गुरुवार (14 दिसंबर) को यूरोपीय संघ के बजट से यूक्रेन के लिए 54 बिलियन डॉलर (50 अरब यूरो) के सहायता सौदे को रोक दिया हंगरी के पीडी एफ विक्टर ओर्बन ने अपना कदम पीछे खींच लिए खींच लिया और डील को अगले साल जनवरी तक के लिए टाल दिया ओर्बन ने एक्स यह जानकारी ज्ञा की और कहा कि उन्होंने डील पर वीटो कर दिया है। उन्होंने ने सोशल मीडिया पर लिखा, नाइटशिप का सारांश: यूक्रेन को अतिरिक्त धन के लिए वीटो, एमएफएफ (बजट) समीक्षा के लिए वीटो, हम उचित तैयारी के बाद अगले साल यूरोपीय परिषद में इस मुद्दे पर वापस आयेंगे।



કિશન ભાવનાના ગાદયા

है ज विचित्र बात ! लिव इन रिलेशन

लिव-इन रिलेशनशिप अर्थात् 'स्वैच्छक सहवादाएँ देखा गए कामों पारावा दापिल हो जाती हैं।

हनार दरा भ कानूना मान्यता हासल हा पुका ह
में लिव-इन रिलेशनशिप को 1978 में कानूनी

मिला था। उस समय बद्रा प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ़ कंपनीजे आपको मार्गदर्शन में शार्फ़ी का नाम दिया

देश मे क्या खूखार डॉग्स को पालने मे लगेगी रोक?

पिटबुल हाई कान जाने पाइ और उन्होंने और हमले) की घटनाओं पर सख्त है में खतरनाक कुत्तों को रखने के मुद्दे चुका है। हाई कोर्ट ने पिटबुल, टेरियर्स और रॉटविलर जैसे खतरनाक नस्लों को लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द सरकार को तीन माह के अंदर निर्णय अदालत ने याचिकाकर्ता बैरिस्टर लॉ जल्द से जल्द विचार करने को कहा कुत्तों के काटने और हमला करने से जा चुकी है। चिंता की बात यह है विलाइसेंस के ही खतरनाक नस्ल के बढ़ते हैं। याचिका में कहा गया था कि ऐसे न मालिकों सहित अन्य लोगों पर भी हमले फर्म ने अदालत का ध्यान दिलाया कि कुत्ते अधिनियम (1991) में पिटबुल के लिए सूचीबद्ध किया गया था। टाइट अमेरिका में पिटबुल और टेरियर्स आबादी का केवल छह प्रतिशत है तो कुत्तों के 68 प्रतिशत हमलों और 52 इसी नस्ल के डॉग जिम्मेदार हैं। याचिका पर पिट बुल ऐंड डेरियर्स अन्य कुत्तों होते हैं। ऐसे कुत्तों को प्रतिबंधित करने पोषण के लाइसेंस को रद्द करना समय में दावा किया गया कि यह केंद्र और कर्तव्य है कि लोगों के हित में काम करने वालों के कुत्तों के काटने की किसी जोखिम से नागरिकों के जीवन को बचाए जाए। दरअसल ऐसे डॉग्स से जुड़े हो रहा है। जो लोग खतरनाक नस्लों

उत्तर द्रुता का जाना होता है, उनका जाना जाना है। वह अवस्थूबर और अहम आदेश दे अमेरिकन बुलडॉग कुत्तों को रखने के रखने के मुद्दे पर केंद्र लेने के लिए कहा। नर्म के प्रतिवेदन पर इसका अनुसरण। दरअसल देश में कई लोगों की जान कुछ लोग तो बिना तो को पाल लेते हैं लेकिन कुत्तों ने अपने यहाँ किया है। इस लॉ बिटेन के खतरनाक और टेरियर को लड़ाई मैगजीन के अनुसार एक संख्या कुत्तों की केन वर्ष 1982 से तेशत मौतों के लिए के अनुसार आमतौर पर ज्यादा आक्रामक और उनके पालन-की मांग है। याचिका राज्य सरकार का और ऐसे खतरनाक भी बड़ी घटना के जाने के लिए प्रभावी नव जीवन पर प्रहार के कुत्ते पालते हैं,



हाई कोर्ट ने पिटबुल, टेरियर, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटविलर जैसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को तीन माह के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा। अदालत ने याचिकाकर्ता बैरिस्टर लॉ फर्म के प्रतिवेदन पर जल्द से जल्द विचार करने को कहा है।



एकशन लेने आदेश दिया था। कुत्तों के काटने के कारण हुई मौतों में करीब 36 फीसदी लोगों की मौत रेबीज की वजह से होती है। बड़ा तथ्य यह है कि अधिकांश मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते। भारत में सबसे ज्यादा लावारिस कुत्ते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कानून है ऐसे डॉग्स को मारा नहीं जा सकता। इसकी वजह से इनकी संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे मानव जीवन पर संकट बना हुआ है। इसके अलावा

राजा राम नहीं जाना बाज तरह राज कर राजा जाना जाना जा रही है। इसके बचाव लिए सरकारों के पास कई भी प्लान नहीं हैं। दुखद यह है कि वाघ बकरी के मालिक पराग देसाई भी डॉग अटैक का शिकार होकर चल बसे। इस हाई प्रोफाइल व्यक्ति की मौत पर कई दिनों तक चर्चा हुई। हालांकि देश में हर रोज़ ऐसी सैकड़ों मौतें होती हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में एक प्रोफेसर को कुत्तों ने नोच-नोच कर मार डाला था। दरअसल ऐसी मौतें को हत्या नहीं माना जा सकता, लेकिन यदि इसकी गंभीरता को समझा जाए तो यह सवालों के घेरे में संबंधित विभाग आता है, क्योंकि लावारिस कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए अच्छा खासा बजेट होता है। कई बार तो ऐसी खबरें सामने आई हैं जब छोटे बच्चों को भी कुत्तों ने नोच कर खा लिया। बीते दिनों एक खाना देने वाले डिलीवरी बॉय को पीछे कुत्ते पड़ गये। वह जान बचाकर भागा। मोर्टरसाइकिल की गति तेज़ कर दी। इससे बैलेंस नहीं बन पाया और एक खिंचे से टकरा कर बेमौत मारा गया। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा लावारिस कुत्तों के हमले भारत में होते हैं। इस मामले में याचिकाकाता बैरिस्टर लों फर्म ने आरोप लगाया था कि खतरनाक नस्लों के कुत्ते भारत सहित 12 से अधिक देशों में प्रतिबंधित हैं, लेकिन दिल्ली नगर निगम अभी भी इनका पंजीकरण पालतू जानवर के रूप में कर रहा है। ऐसे कुत्तों की खरोद-फरोख करने वालों को भी यह समझना होगा कि वह इन नस्लों को आगे न बढ़ाएं और पालें। दरअसल देशभर के तमाम लोग खतरनाक कुत्तों को प्रजनन करके उनको बेचने का व्यापार करते हैं। यदि सरकार इनको रखने के लिए लाइसेंस नहीं भी देगी तो वह चोरी से इनको रखेंगे। इसलिए सरकार को इसके लिए विशेष अतिरिक्त विभाग बनाकर बड़ा काम करना होगा।

अब कौन पहुंचायेगा सरकारी संपत्ति को नुकसान?

जिस बात का देश से प्रेम करने वाले होके नागरिक को दशकों से इंतजार था, वह अब हो गई है। अब किसी आंदोलन के दौरान कथित आंदोलनकारी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि नुकसान पहुंचाया तो उन्हें सख्त सजा होगी। हमारे यहां सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करने वाले आमतौर पर सरकारी बसों, इमारतों, रेलों और दूसरी सार्वजनिक संपत्तियों को बेशर्मी से तोड़ते रहे हैं। कहना न होगा आजाद भारत में इस कारण से सत्तर सालों में अरबों-खरबों रुपये का नुकसान हुआ। जिन्हें नुकसान किया उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। वे दशकों से मौज करते रहे। उनमें से कई बड़े नेता भी बन गये। पर अब आगे किसी ने सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचाई तो लेने के देने पड़ जायेंगे। इसलिए ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की ओर से पिछले मंगलवार को संसद में पेश भारतीय न्याय सहिता विधेयक, 2023 के अपडेटेड वर्जन में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसमें ‘आतंकवादी कृत्य’ में देश की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता पर हमले भी शामिल किये गये हैं। संसद की स्थायी समिति की ओर से सुझाये गये संशोधनों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में सदन में पेश किये गये भारतीय न्याय सहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को वापस लेने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने मंजूरी दी। इसके बाद उन्हें नये विधेयकों को पेश किया। भारतीय न्याय सहिता विधेयक की धारा 113(1) में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा या हरकत करता है, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान या खतरा पैदा होता है, या आतंकी घटना की मंशा रखता हो, आतंकी हमले करता हो, इसके लिए बम, हथियार, केमिकल, बॉयोलॉजिकल हथियार और जहर आदि का इस्तेमाल करता हो, जिससे जान-माल का नुकसान हो तो मामले में दोषी शाख्स को उम्रकैद या फांसी की सज हो सकती है। भारतीय न्याय सहिता विधेयक की 113(5) में कहा गया है कि अगर कोई शख्स की रक्षा परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो या अन्य की सरकार की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो तो वह आतंकवाद यानी टेरर एक्ट माना जायेगा। इसी कानून की धारा 113(बी) में कहा गया- अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे या पब्लिक फंक्शनरी पर हमला करता है या अगवा करता है या ऐसी मंशा रखता है तो ऐसे मामले को भी टेरर एक्ट माना जायेगा। इससे मौत होने पर उम्रकैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। आपको याद होगा कि नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूख भी अछित्यार कर लिया। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया के ने भी विरोध प्रदर्शन के दौरान बसें और दूसरी गजला दीं थीं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि छात्रांशांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कोर्ट ने इसके दौरान हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर न जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के

ऐसे तक धारा गारत तरह जलाने का अधिकार किसने दे दिया? कोर्ट ने छात्रों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी बात खबरे के लिए उन्हें सड़क पर उतरने का अधिकार तो है लेकिन, वो अगर सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करेंगे तो कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा। अकसर विरोध प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है। कभी बसें जला दी जाती हैं, कभी ट्रेनों पर पथराव होता है, कभी सरकारी इमारतों में तोड़-फोड़ होती है, तो कभी सरकारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का नुकसान किया जाता है। ये सबाल बार-बार पूछा जाता था कि अगर विरोध प्रदर्शन में सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब स्थिति साफ हो गई है। अब किसी ने सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई तो लेने के देने पड़े जायेंगे। कहना ना होगा कि विरोध प्रदर्शन के कारण भारतीय रेलवे को तो हमेशा बलि का बकरा छात्रों ड्यूयां को रशन बुशी बसें ही समझा जाता है। रेलवे को पिछले तीन सालों में लगभग 262 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा है और रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान 2022 में हुआ है। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते तीन सालों में यारी कि 2020, 2021 और 2022 में भारतीय रेलवे को 1.78, 0.68 और

259.44 करोड़ रुपये का नुकसान विरोध प्रदर्शनों के दौरान रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचने के कारण हुआ है। 2022 में भारतीय सेना द्वारा सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लाई गई थी जिसका देश के कई राज्यों में काफी विरोध हुआ था। उस समय रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ की कई घटनाएं सामने आई थीं। वहाँ कई ट्रेनों को भी प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया था। दरअसल सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून पहले भी था। उसे सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 कहते थे। इसके प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी साबित होता है तो उसे 5 साल की सजा हो सकती थी। इसमें जुमानि का भी प्रावधान था। ऐसे मामलों में दोषी पाये जाने पर सजा और जुमाना दोनों हो सकता था। पर पुराना कानून कमज़ोर पड़ रहा था या कहें कि उसका असर नहीं हो रहा था। इसलिए नये और सख्त कानून की दरकार थी। सुप्रीम कोर्ट को भी हमेशा लगता रहा कि इस मामले में और भी उपाय किये जाने की ज़रूरत है। 2007 में सार्वजनिक संपत्ति के भीषण नुकसान की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस वक्त हिंसक विरोध प्रदर्शन, बंद और हड्डाताल में सरकारी संपत्ति का खूब नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कानून में बदलाव के लिए दो कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थार्मस और सनियर वकील फली नरीमन को कमेटियों का प्रमुख बनाया गया था। 2009 में इन दोनों कमेटियों की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्ति को लेकर कुछ गाइड लाइंस जारी किये थे। कहना न होगा कि अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि सरकारी संपत्ति से तोड़फोड़ करने से पहले देश के दुश्मन 10 बार सोचेंगे। (लेखक, वरिष्ठ संपादक, संभक्ता और पूर्व सांसद हैं।)

— 1 —

पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखण्ड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155, प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्धन बजाज, कार्यकारी संपादक : सुनील सिंह 'बादल'*, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेडमा, मेदिनीनगर (डालतनगंज) पलामू-822102, फोन नंबर : 222539, फैक्स नंबर : 06562-241176/ 231257, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान हरमू रोड, रांची-834001, फोन नंबर : 0651-2283384, फैक्स नंबर : 0651-2283386, ई-मेल : news.rnmail@gmail.com, article.rnmail@gmail.com (*पीआबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

एक नजर

उर्जा मित्रों को आठ माह से नहीं मिल रहा मानदेय

लातेहार। लातेहार शेत्र के उर्जा मित्रों को पिछले आठ माह से मानदेय नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उर्जा मित्रों के फेरेशनियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो अल्प मानदेय (कमीशन) पर उर्जा मित्र काम रहे हैं, ऊपर से उनको आठ माह से मानदेय नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार, कार्यकारी एजेंसी सार्थ कंचूटर (मेदिनीगढ़) को प्रति माह प्रमंडल से विपत्र का भुगतान किया जाता है, लेकिन एजेंसी उर्जा मित्रों को भुगतान नहीं कर रही है। कई उर्जा मित्रों ने बताया कि मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है। उर्जा मित्रों ने विद्युत कार्यपालक अधिकारी मो शमसान आलम से मानदेय भुगतान कराने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया है।

नगर प्रशासक की अपील खुले में ना फेंके कचरा

लातेहार। लातेहार नगर प्रशासक राजीव रंजन ने नगर वासियों से खुले में कचरा नहीं फेंकने की कहाँ है। उर्ध्वाने नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाने में नगर पंचायत का सहायता करने को कहा है। राजीव रंजन ने कहा कि नगर पंचायत की गतिविधि उठाने में डोर दूरों करके उठाने जाते हैं। लोग नियंत्रित रहने पर ही कचरा फेंके, ताकि नगर पंचायत कर्मियों को करार उठाने में सहुलियत हो। कहा कि वाहन कम होने के कारण वार्ड के अंदर की गलियों में वाहन नहीं जा पहा है। उर्ध्वाने कहा कि वाहन उपलब्ध करने के लिए विधायक से पत्राचार किया गया है। सीधी ही शहर के हर वार्ड के सभी गलियों में वाहन प्रवेश करें।

जेएसएलपीएस कर्मियों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन

लातेहार। जेएसएलपीएस के एल-5 और 6 कर्मियों ने डीसी व डीडीली लातेहार को अपने तीन दिवसीय हड्डताल के दूसरे दिन एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि अन्य मार्गों को लेकर वे बिताया दो वर्षों से सघरित हैं। इस संबंध में प्रबंधन से कई बार पत्राचार किया गया है। लेकिन प्रबंधन को इसका विपरीत है।

इस कारण वार्ड हड्डताल कर रहे हैं।

हड्डताल होने से गांव से लेकर प्रखंड एवं जिला स्तर की समस्त ग्रामीण विकास की गतिविधियां प्रभावित हो गयी हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले तक वार्डों में जानकारी नहीं होती है वे हड्डताल पर रहे, जान सौंपने वालों में अकेत कुमार, मनोज कुमार, आदि का नाम शामिल है।

होमगार्ड बहाली में आधी आबादी का उत्साह चरम पर

मेदिनीगढ़। शहर के पुलिस स्टेटिव्यां में जिलावार को भी होमगार्ड महिला जवानों की बहाली प्रक्रिया जारी रही। जिलावार को पलामू जिले के हुसैनाबाद, मुहम्मदगज, नौदिङाराज, छत्तेपुर सहित अन्य प्रखंडों के लालगढ़ 1000 से अधिक महिला अध्यार्थी शामिल हो गए होमगार्ड बनने के लिये सभी अध्यार्थी उत्साहित दिखे। चयन प्रक्रिया में पुलिस स्टेटिव्यां में मैरिन सौंप दै भैं में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग किया जा रहा है।

पूर्व सैनिकों ने मनाया विजय दिवस



छहमुहान पर विजय दिवस मनाते पूर्व सैनिक

वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति व वीर रस से ओत-प्रोत कवि गोषी का आयोजन किया गया

नवीन मेल संवाददाता मेदिनीगढ़। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा वर्ष 1971 में भारत की पाकिस्तान पर अभ्यूपर्व व ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में

शनिवार को विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहर के डा. राजेंद्र प्रसाद चौक (छो मुहान) पर आयोजित समारोह में युद्ध का हिस्सा रहे सैनिकों को समानित किया गया। इस दौरान वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति व वीर रस से ओत-प्रोत कवि गोषी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक

से हुयी। तत्पश्चात पलामू के लाल मनु अख्यारी, युवाकर दोषांश, प्रवाध भेदहस्त को प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही आजारी के बाद हुई लड़ाईयों में अपने प्रापां का न्यायालय करने वाले शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अपनित की गई। कार्यक्रम में युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक

संत मरियम स्कूल उत्कृष्ट छात्रों को देगा स्कॉलरशिप

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के लिए विद्यालय के उपलक्ष्य में

आयोजनामूलक विद्यालय नामांकन प्रक्रिया के

